‘सहकारिता में सहकार’ को बढ़ावा देने की राष्ट्रव्यापी पहल

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 04 – अंक : 02 – मई 2026

सहकार से समृद्ध हो रही हिमालयी राज्यों की

कोऑपरेटिव डेयरी

ढाई हजार वर्षों बाद भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं 14

बनारस के आठ गांवों के किसानों का समूह दूसरों के लिए बना मिसाल 29

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

मई 2026, अंक 02, वर्ष 04

संपादक मंडल

संपादक

राजीव शर्मा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें :
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते :

Ministry of Cooperation

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

06 आवरण कथा

सहकार से समृद्ध हो रही हिमालयी राज्यों की कोऑपरेटिव डेयरी

प्राकृतिक रूप से कठिन जलवायु और ऊंचाई वाले हिमालयी राज्यों में सहकारी डेयरी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एंड टू एंड साल्यूशन देने की घोषणा की है। इससे लद्दाख समेत अन्य सभी हिमालयी राज्यों में डेयरी का समग्र विकास होगा।

17

जैविक व प्राकृतिक खेती का सिक्किम मॉडल पूरे देश के लिए है प्रेरणा

सिक्किम में पर्यटन रोजगार का एक प्रमुख साधन है। इससे बड़ी मात्रा में आय होती है और और पर्यटन तभी फलता-फूलता है जब इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हाल के वर्षों में राज्य में सैकड़ों किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है और हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है।

मुंबई में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर 25000 ड्राइवर हुए ऑनबोर्ड **18**

नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को सरकार प्रतिबद्धः श्री नरेन्द्र मोदी **20**

'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने की राष्ट्रव्यापी पहल **22**

शुद्ध, पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण मसालों का बड़ा केंद्र बना जयपुर **27**

असम में महिला किसानों को समृद्ध बना रहा स्वरंग एफपीओ **28**

29

बनारस के आठ गांवों के किसानों का समूह दूसरों के लिए बना मिसाल

पांच वर्षों में 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव

श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत ने दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनने का सफर तय किया है। अब श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से भारत को शीर्ष दूध निर्यातक बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने तय किया गया है। इसमें सहकारिता क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। इस कड़ी में देशभर में तेजी से डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है और 75 हजार नई डेयरी कोऑपरेटिव बनाई जा रही है। मोदी सरकार लद्दाख में भी सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही है।

हिमालय की गोद में बसे लद्दाख में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और सहकारिता को सुदृढ़ करने के मकसद से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कारगिल में 10 हजार लीटर प्रति दिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास करने के साथ लेह में दही एवं पनीर उत्पादन सहित नई डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों और दूध व डेयरी टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा देश के बाजारों तक स्थानीय दुग्ध उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। सहकारी क्षेत्र में डिजिटल सशक्तीकरण के विजन को और मजबूत करते हुए खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा किसानों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दूध के भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एंड्रॉयड-आधारित ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम (एएमसीएस) एप्लिकेशन भी शुरू किया गया। इससे दुग्ध उत्पादक अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर पारदर्शिता के साथ देख पाएंगे।

कोऑपरेटिव डेयरी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, कोल्ड-चेन प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय डेयरी किसानों के लिए बाजार संपर्क को विस्तारित करने की दिशा में ये कदम महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये कदम लद्दाख की सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने तथा देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही कारगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहां के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। डेयरी सहकारिता के माध्यम से लद्दाख में पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र के 85 प्रतिशत गांवों तक डेयरी के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

यह परिवर्तनकारी पहल लद्दाख में विकास और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है और पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के उज्ज्वल भविष्य का नया मार्ग प्रशस्त कर रही है। हिमालयी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और सुविधाओं की चुनौतियों के बीच यह पहल साबित करती है कि मजबूत इच्छाशक्ति और सहकारिता से हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। यह लद्दाख की नई समृद्ध पहचान बन रही है।

देशभर में डेयरी कोऑपरेटिव की योजनाएं न केवल डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय वृद्धि और महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। सहकारी मॉडल के जरिए छोटे किसानों और पशुपालकों को बाजार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

जय सहकार

देशभर के अपने अन्नदाता भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। इससे जहां करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा, वहीं चीनी मिलों और इस क्षेत्र से जुड़े लाखों श्रमिकों को भी फायदा मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

बीते साढ़े पांच दशकों से सहकारिता की शक्ति को धरातल पर उतारने वाली मधुर डेयरी प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संकलन कर देश की सहकारी डेयरियों के लिए एक आदर्श बन रही है। केंद्र सरकार सहकारी डेयरी क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, नवाचार और मूल्य संवर्धन के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ जनभावनाओं और जनसंवाद की सशक्त भाषा है। सहकारिता का मूल भाव भी जनभागीदारी, सामूहिक प्रयास और साझा समृद्धि में निहित है। ऐसे में सहकारिता आंदोलन को सरल, सहज और प्रभावी हिंदी के माध्यम से गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवच लगातार मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी जनहितकारी सुरक्षा बीमा योजनाओं से करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और भरोसे का संबल मिल रहा है।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। उनकी खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उन्हें ऋण देने और टैक्स माफ करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में किसानों के विकास के लिए सहाकारिता मंत्रालय संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डेयरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को दी एक नई पहचान

सहकार जागरण टीम

पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के बिना जीवन एक पल भी संभव नहीं है। यह ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। भारत ने हाल ही में इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। इससे भारत दुनिया के अग्रणी चार देशों में शामिल होते हुए विंड एनर्जी में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन गया है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 133वें एपिसोड में कही। उन्होंने कहा कि यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नए कौशल विकसित हो रहे हैं, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है - ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा अपनाना है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं। क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।

दुनिया से भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है और स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनाव और संघर्ष से गुजर रही है, उसमें बुद्ध के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। जनगणना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। इस बार जनगणना का अनुभव अलग होने वाला है।

देश में डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। आज भारतीय चीज दुनिया-भर में अपनी जगह बना रही है। दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू-कश्मीर की कलारी चीज को 'कश्मीर का मोजेरेला' कहा जाता है। गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में 'छुरपी' बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इसकी खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है।

पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों को अष्टलक्ष्मी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यहां भरपूर प्रतिभा है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। कभी बोझ के रूप में देखा जाने वाला पूर्वोत्तर का बंबू सेक्टर आज रोजगार, कारोबार और नवाचार को नई गति दे रहा है। हमारी माताएं-बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। कानून में बदलाव कर बंबू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर निकालने के बाद यह सेक्टर फल-फूल रहा है। यह क्षेत्र वैल्यू एडिशन के साथ ही लगातार नवाचार कर रहा है। विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखे जाने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारे उद्योग, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक नवाचारों को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी।■

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लद्दाख में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहकारिता की पहलों का किया शुभारंभ

सहकार से समृद्ध हो रही हिमालयी राज्यों की कोऑपरेटिव डेयरी

सहकार जागरण टीम

प्राकृतिक रूप से कठिन जलवायु और ऊंचाई वाले हिमालयी राज्यों में सहकारी डेयरी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एंड टू एंड साल्यूशन देने की घोषणा की है। इससे लद्दाख समेत अन्य सभी हिमालयी राज्यों में डेयरी का समग्र विकास होगा। यहां के दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों और किसानों के लिए उत्कृष्ट प्रजाति के दुधारु पशु उपलब्ध कराये जाएंगे। डेयरी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले

कोऑपरेटिव डेयरी को प्रोत्साहन, दुधारु पशुओं के स्वास्थ्य का होगा विशेष जोर

खुलेंगे उच्च स्तरीय प्रजनन केंद्र, किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे हाईब्रिड प्रजाति के दुधारु पशु

मोबाइल दुग्ध कलेक्शन वैन से सुदूर गांवों में होगी दूध की खरीद

वैज्ञानिकों की मदद से यहां उच्च स्तरीय प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें हाईब्रिड प्रजाति के दुधारु पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। इसस यहां के दुधारु पशुओं की दूध देने की क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि की जा सकेगी। यहां के दूध की खरीद प्रमुख सहकारी संस्थाएं करेंगी। सुदूर बसे गांवों और बस्तियों तक से दूध कलेक्शन के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मोबाइल दुग्ध कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और दूध की गुणवत्ता मापने मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई। इससे लद्दाख के पशुपालकों को लाभ प्राप्त होगा।

यहां के दुग्ध उत्पादों के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। लद्दाख जैसी विषम परिस्थिति में दुग्ध उत्पादन करने वाले पशु पालकों को डेयरी उद्योग स्थापित करने के लिए कई तरह की मदद भी दी

> “कारगिल में 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 10 टीएलपीडी क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी गई और लेह मिल्क प्लांट के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। भारत सरकार, एनडीडीबी और लद्दाख प्रशासन द्वारा स्थापित यह परियोजना किसानों और पशुपालकों की आत्मनिर्भरता को गति प्रदान करेगी।
>
> -श्री अमित शाह
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री”

करगिल में 25 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता वाले डेयरी प्लांट की नींव

लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी के बीच हुई साझेदारी से देश के बाजारों तक स्थानीय दुग्ध उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी

लद्दाख में पश्मीना, ऑर्गेनिक उत्पादों और शहद के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित होंगी

जाएगी। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य के लिए वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध कराने के साथ दुग्ध प्रसंस्करण के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी।

सहकारी डेयरी से आईटीबीपी और सेना खरीदेगी दुग्ध उत्पाद

लद्दाख में आईटीबीपी और सेना कोऑपरेटिव डेयरी से दूध, दही और पनीर के बहुत बड़े खरीददार हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि यहां सीमा पर 18,000 जवान रहते हैं और इन जवानों को दूध, दही और पनीर की सप्लाई इसी सहकारी डेयरी के माध्यम से की जाएगी। श्री शाह ने 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक मोबाइल दूध परीक्षण प्रयोगशाला भी लॉन्च किया और कहा कि इससे दूध की क्वालिटी के रखरखाव में बहुत फायदा होगा। इससे क्षेत्र में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और जमीनी स्तर पर डेयरी किसानों को सहयोग मिलेगा। दूध और उन्य उत्पादों की आपूर्ति कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटियां करेंगी, जिससे यहां के किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में

“ भारत के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में 'वैल्यू एडिशन' ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। आज भारतीय 'चीज' दुनिया-भर में अपनी जगह बना रही है। ब्रेकफास्ट हो या लंच या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू-कश्मीर की कलारी 'चीज' को ही लीजिए, इसे 'कश्मीर का मोजेरेला' कहा जाता है। गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोग, पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में 'छुरपी' बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री ”

सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न पहलों के माध्यम से सहकारिता आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने का अभियान तेज कर दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्र में सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए श्री अमित शाह ने लेह के केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान में विभिन्न सहकारी पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कोऑपरेटिव डेयरी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, कोल्ड-चेन प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय डेयरी किसानों के लिए बाजार संपर्क को विस्तारित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इन परियोजनाओं में सहकारी डेयरी संचालन के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल एवं संस्थागत पहलों का शुभारंभ भी शामिल हैं। सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के ये पहल ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने तथा देश के दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कारगिल में 10 हजार लीटर प्रति दिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने लेह में दही

लद्दाख में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा विस्तार

पूरे देश में हो रहे सहकारिता के विस्तार के साथ ही लद्दाख में डेयरी कोऑपरेटिव पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा, 'हम लद्दाख में डेयरी अवसंरचना का विस्तार कर रहे हैं। लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वह लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही करगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहां के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। यहां के मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराने का काम होगा। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा।' श्री शाह ने कहा कि यहां दैनिक दूध की खरीद लगभग 7000 किलोलीटर तक पहुंची है। अगले चार वर्षों में इसे 21,000 किलोलीटर तक पहुंचाकर यहां के किसानों की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी में समझौता होने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हैं।

देशभर में डेयरी कोऑपरेटिव की योजनाएं न केवल डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय वृद्धि और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है। सहकारी मॉडल के जरिए छोटे किसानों और पशुपालकों को बाजार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

सहकार से समृद्धि की नई मिसाल

हिमालय की गोद में सहकारिता के नए युग का श्री अमित शाह ने किया शुभारंभ

लेह में सहकारिता की शक्ति का शंखनाद

कारगिल का आधुनिक डेयरी प्लांट बना रोजगार, महिला सशक्तीकरण और पहाड़ी सीमाओं पर सेवाओं का मजबूत आधार

एवं पनीर उत्पादन सहित नई डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन भी किया। श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र में डिजिटल सशक्तीकरण के विजन को और मजबूत करते हुए खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा किसानों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दूध के भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एंड्रॉयड-आधारित ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम (एएमसीएस) एप्लिकेशन शुरू किया और कहा कि इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालक अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर पारदर्शिता के साथ देख पाएंगे। इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के मन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा।

उन्होंने 'बल्क मिल्क कूलर प्रणाली' का भी शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि आगामी 10 साल में पशुओं की संख्या में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी करने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को लोगों का अच्छा लाभ मिलेगा। श्री शाह ने लद्दाख के प्रशासन का आह्वान किया कि लद्दाख के हर गांव में, जहां दूध उत्पादन और पशुपालन की संभावना है, डेयरी के विस्तार को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहकारिता विभाग यहां पश्मीना, ऑर्गेनिक उत्पादों और शहद से संबंधित सहकारी समितियों की स्थापना करेगा।

दो करोड़ दुग्ध उत्पादकों ने डेयरी सेक्टर को दी नई ऊंचाई

देश में पिछले वर्षों में हुए उल्लेखनीय डेयरी विकास पर जोर देते

कोऑपरेटिव डेयरी से कारगिल की महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर

श्री शाह ने कहा कि 2014 में श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सहकारिता मॉडल के तहत लद्दाख क्षेत्र में विकास के लिए एक साथ शुरू किए गए विभिन्न पहलों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि करगिल जैसी ऊंचाई वाले जगह पर डेयरी प्लांट के शुरू होने पर करगिल की महिलाएं अपने जीवन में उजाला ला सकती हैं। परिवार की मदद कर सकती हैं। उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। क्षेत्र में डेयरी विकास की असीम संभावना है। डेयरी से जुड़कर महिलाएं निश्चय ही अपने परिवार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई में योगदान कर सकेंगी। डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से गुजरात की महिलाओं की सफलता का उदाहरण देते हुए श्री शाह ने कहा कि ऐसी ही छोटी-छोटी डेयरियों के माध्यम से वहां महिलाओं ने 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया है। श्री शाह ने कहा कि यहां 25 करोड़ की लागत से जिस नई परियोजना की शुरुआत हो रही है, वह निश्चित रूप से करगिल की माताओं-बहनों के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि लेह में पहले से काम कर रहे 'मिल्क प्लांट' में प्रतिदिन डेयरी उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही है।

श्री शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ने एक समझौता किया है। इससे लद्दाख को देश के बाजार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे स्थानीय डेयरी उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे और किसानों को उचित मूल्य मिलना भी सुनिश्चित होगा। लद्दाख के ऑर्गेनिक उत्पादों को दिल्ली के बड़े बाजार तक पहुंचाने की अपील करते हुए श्री शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का आह्वान किया कि वह नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय एमओयू करके इसे साकार करे। उन्होंने मदर डेयरी का आह्वान किया कि वह अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से देश भर में लद्दाख के डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करे।

श्री शाह ने क्षेत्र के प्रगतिशील डेयरी किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने जिन पांच पशुपालकों को पुरस्कृत किया है, वे करगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप हैं। सरकार के ये सभी पहल सहकारिता के जरिए सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और देश के दूरदराज के क्षेत्रों में समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहे।

लद्दाख में सहकारिता का नया आगाज

सहकारिता की शक्ति बर्फीले रेगिस्तान के किसानों की उम्मीदों को नया आसमान दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में प्राकृतिक चुनौतियों से घिरे करगिल में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक डेयरी प्लांट प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग क्षमता के साथ स्थानीय लोगों के लिए समृद्धि लेकर आया है। यह परिवर्तनकारी पहल लद्दाख के विशाल क्षेत्र में विकास और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है और पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के उज्ज्वल भविष्य का नया मार्ग प्रशस्त कर रही है। डेयरी सहकारिता के माध्यम से लद्दाख में पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र के 85 प्रतिशत गांवों तक डेयरी के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में क्षेत्र के 28 गांवों के 1700 दुग्ध उत्पादक किसान डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं जो करीब 7000 किलोलीटर दूध का योगदान कर रहे हैं। सरकार ने आगामी चार वर्षों में 21,000 किलोलीटर प्रतिदिन दूध का लक्ष्य तय करके किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। डेयरी क्षेत्र में ये सहकारी पहलें उत्पादन वृद्धि, डिजिटल सशक्तीकरण और बाजार से सशक्त जुड़ाव के माध्यम से नई विकास गाथा रच रही हैं। हिमालयी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और सुविधाओं की चुनौतियों के बीच यह पहल साबित करती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और सहकारिता से हर कठिनाई को अवसर में बदला जा सकता है। यह लद्दाख की नई समृद्ध पहचान बन रही है।

हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान जहां वर्ष 2014-15 तक भारत का कुल दूध उत्पादन 146 लाख टन ही था, वहीं वर्ष 2024-25 तक यह 146 लाख टन से बढ़कर 248 लाख टन हो गया है। इसतरह, पिछले 10 वर्षों में देश में दूध उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसमें से 50 प्रतिशत वृद्धि पिछले पांच वर्षों में हुई है। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वर्ष 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी, वह अब 485 ग्राम हो गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 2,36,000 सहकारी समितियों और लगभग दो करोड़ दूध उत्पादकों के माध्यम से ही हमने यह उपलब्धि प्राप्त की है। श्री शाह ने कहा कि हमने पांच वर्षों में 75,000 नई डेयरी समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 21,000 नई समितियां बनाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही, देश भर की 46,000 मौजूदा समितियों को भी आधुनिक व सक्षम बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास पर सरकार का फोकस

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि लेह-लद्दाख और करगिल की बहुत पुरानी मांग थी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए।

> लद्दाख में एक मोबाइल लैब, बल्क मिल्क कूलर और ऐप आधारित दूध संग्रहण प्रणाली का शुभारंभ किया। ये पहलें किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम हैं, जिससे उन्हें वास्तविक समय में भुगतान, दूध संग्रहण और गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा मिलेगी।
>
> -श्री अमित शाह
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जहां अब सात जिले और 193 पंचायतें हो गई हैं। शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास के नाम से पांच नए जिले हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। क्षेत्रीय लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यहां की स्थानीय भाषा को भी प्रशासन की भाषा बनाया गया है, जिससे भोगी, पुर्गी, ऊर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व मिला है।

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में विकास कार्य मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार हैं। लद्दाख में हो रहे तेज विकास का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 2019 से पहले इस क्षेत्र में 1,800

हिमालयी राज्यों की डेयरी के दुग्ध उत्पादों के निर्यात की पर्याप्त संभावना

लेह में दही और पनीर उत्पादन के लिए नई प्रोसेसिंग इकाइयों और दूध व डेयरी टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैबोरेटरी का उद्घाटन

किलोमीटर सड़कें थीं, जो आज 4,040 किलोमीटर हो गई हैं। पहले जहां क्षेत्र में 19 पुल थे, आज 72 पुल बन चुके हैं। संचार नेटवर्क के लिए जहां पहले 344 मोबाइल टावर थे, आज 653 हो गए हैं। ग्रिड से जुड़े गांव जहां पहले 145 थे, वे बढ़कर आज 184 हो गए हैं। क्षेत्र में पहले केवल 1,182 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे जो आज 3,153 हो गए हैं। वहीं, हवाई यात्रा की सुविधाओं के लिए जहां पहले केवल सात हेलीपैड थे, अब 41 बन गए हैं। क्षेत्र में बर्फ हटाने के लिए पहले की सात मशीनों की जगह आज 215 मशीनें काम कर रही हैं। बर्फ हटाने वाली इन मशीनों और अन्य संरचनाओं के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जोजिला सुरंग का काम प्रगति पर है और सिंकुला सुरंग का काम शुरू हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि जोजिला दर्रा जहां वर्ष में 127 दिनों बंद ही रहता था, वह इस बार सिर्फ 19 दिन बंद रहा। कारगिल-जांस्कर मार्ग 154 दिन बंद रहता था, वह सिर्फ 11 दिन बंद रहा।

लद्दाख क्षेत्र में नया नागरिक हवाई अड्डा बनने का काम भी शुरू हो गया है। सभी पंचायतों में बेहतरीन संचार सुविधाएं शुरू कर दी गई है और 4जी टावरों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण काम भी हुआ है। सरकार ने यहां सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। साथ ही, 174 आईसीटी लैब स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र में 230 स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं। वहीं, 40 खगोल विज्ञान लैब भी बने हैं। 24 अटल टिंकरिंग लैब बनी हैं और लद्दाख 2024 में पूर्ण साक्षर बनने वाला प्रशासनिक यूनिट बन गया है, जहां अब कोई अनपढ़ नहीं है। इश केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 98 प्रतिशत घरों को 'हर घर जल योजना' से जोड़ दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्र में कृषि और बागवानी के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है। इन विकास कार्यों को तेज करने के लिए लद्दाख का बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपए हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख जब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, तब मात्र 1,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, लेकिन यहां आज भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि हमने सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की है, जो औद्योगिक विकास के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। सरकार चाहती है कि यह सीमांत प्रदेश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने लद्दाख और करगिल के वासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत पर जब-जब इस सीमा से संकट आया, लद्दाख वालों ने अपने सीने पर गोली खाई और देश की रक्षा की। श्री शाह ने कहा कि भारत स्काउट का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरा देश जानता है। लद्दाख के लोगों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा और इस बहुत बड़े भू-भाग को भारत के साथ जोड़े रखने की तत्परता की देश का हर नागरिक प्रशंसा करता है और लद्दाख के लोगों के प्रति कृतज्ञ भी है।■

अंतरराष्ट्रीय मंच पर जमी भारतीय डेयरी की धाक

भारतीय डेयरी उत्पाद अब घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। ब्राजील में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता-2026' में भारत के हस्तनिर्मित डेयरी के तैयार चीज उत्पादों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि पहली ही बार में ही चार महत्वपूर्ण मेडल जीत लिए। यह उपलब्धि भारतीय डेयरी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो यह प्रमाणित करती है कि भारत अब दूध उत्पादन के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रसंस्कृत उत्पादों में भी विश्व स्तरीय मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र की इस उपलब्धि पर भारतीय चीज निर्माताओं को बधाई दी है। इस सफलता को भारत के आर्टिसनल (परंपरागत) डेयरी सेक्टर के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह जीत भारत के आर्टिसनल डेयरी सेक्टर के तेजी से बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करती है। भारतीय उत्पाद अब सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। यह 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल टू ग्लोबल' की यात्रा का एक सशक्त उदाहरण है। भारत में आर्टिसनल चीज का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये उत्पाद अपनी शुद्धता, हस्तनिर्मित प्रक्रिया और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण प्रीमियम बाजारों में लोकप्रिय हो रहे हैं। ब्राजील में मिली उपलब्धि यह दर्शाती है कि यदि गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो भारतीय उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जीत के बाद भारतीय डेयरी निर्यात में नए अवसरों का सृजन होगा। इससे भारतीय उत्पादों की साख बढ़ेगी। इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

लेह में बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ कर बोले श्री अमित शाह

ढाई हजार वर्षों बाद भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं

सहकार जागरण टीम

- **भगवान बुद्ध का जीवन हमें सत्य, अहिंसा और करुणा के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है**
- **भारतीय संस्कृति और भगवान बुद्ध का महान संदेश, संवाद से समाधान और मध्यम मार्ग की राह दिखाता है**

भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और अहिंसा का संदेश देती आई है। इस भूमि पर सदियों से ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराएं सुरक्षित और जीवित हैं। इनमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और शांति, करुणा एवं मध्यम मार्ग के उनके संदेशों का आधुनिक समय में भी बहुत महत्व है। उनकी शिक्षाएं 2,500 साल पहले की तुलना में दुनिया के लिए वर्तमान समय में कहीं और भी अधिक प्रासंगिक है। केंद्रीय गृह एवं

- लद्दाख केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है
- लद्दाख में बसती है करुणा और शांति की असली पहचान, 75 साल बाद लद्दाख पहुंचे बुद्ध अवशेष
- लद्दाख की विरासत बताती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही अंतिम समाधान दे सकता है

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए रखे जाने के कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किया। लेह में 2569वें बुद्ध पूर्णिमा समारोह का उद्घाटन कर श्री शाह ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की 75 साल बाद लद्दाख वापसी को ''ऐतिहासिक पुनर्मिलन'' बताया और कहा कि यह केंद्रशासित प्रदेश सदियों से ''धर्म की जीवंत भूमि'' रहा है। इसने बौद्ध ज्ञान को सहेजा एवं पोषित किया है।

उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से लाए गए ये अवशेष केवल धार्मिक प्रतीक मात्र नहीं हैं, बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में इसकी पहचान को गहरा करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है। लेह और उसके बाद जांस्कर एवं अन्य केंद्रों में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाने वाले ये अवशेष हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन और शांति के नए द्वार खोलेंगे। श्री शाह ने कहा कि महायान बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि जब पवित्र अवशेषों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, तब बुद्ध का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की तरह शायद ही किसी के जीवन में ऐसा होगा कि जन्म, ज्ञानप्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन हुए हों, इसीलिए हम सबके लिए यह बहुत शुभ और प्रेरणादायक है।

सैकड़ों वर्षों से धम्म की जीवंत भूमि है लद्दाख

लद्दाख सैकड़ों वर्षों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। इस भूमि पर ज्ञान का संरक्षण

और संवर्धन हुआ है। श्री शाह ने कहा कि इतने साल के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे प्रिय भूमि पर लौटे हैं। लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती रही है।

श्री शाह ने कहा, ''जब भी बौद्ध धर्म संकट में पड़ा, इस भूमि ने बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा के लिए काम किया और जब शांति लौटी, तो इसने उस संरक्षित ज्ञान को विस्तार देने और आगे बढ़ाने में मदद की। लद्दाख की धरती से निकला संदेश दुनिया भर के अनेक लोगों के लिए जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरक शक्ति बना है।''

महात्मा बुद्ध के जीवन से मानवता के कल्याण की प्रेरणा

महात्मा बुद्ध के जीवन मूल्यों पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा, ''भगवान बुद्ध का जीवन हमें सत्य, अहिंसा और करुणा के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण हेतु निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका अमूल्य ज्ञान युगों-युगों तक मानव सभ्यता को आलोकित करता रहेगा।''

उन्होंने कहा कि लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग समय पर पहुंचता और पनपता रहा और विकसित होकर लद्दाख से बाहर भी गया है। यहीं से तथागत बुद्ध की शिक्षाएं लद्दाख और इसके आसपास के मार्गों के जरिए चीन तथा कई अन्य देशों तक पहुंचीं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत के ज्ञान और भगवान बुद्ध के महान संदेश को समझ और स्वीकार कर समाधान के रास्ते पर चलना चाहिए और मध्यम मार्ग पर बढ़ना चाहिए।

संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग

श्री शाह ने कहा कि लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान न्यिंग्मा, काग्यु, शाक्य और गेलुग की चार प्रमुख परंपराओं से बनी है। न्यिंग्मा का अर्थ है कि जो जैसा है, उसे वैसा ही देखिए। वहीं, काग्यु का आशय है कि गुरु की कृपा और निरंतर आत्मचिंतन ही मुक्ति का द्वार है। शाक्य यह बोध कराता है कि ज्ञान साधना के बिना अधूरा है और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है, इसीलिए ज्ञान और साधना का मिलन ही सही रास्ता है। गेलुग की परंपरा हमें नैतिक अनुशासन का पाठ पढ़ाती है क्योंकि यदि नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन नहीं बन सकता। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख की भूमि से निकला यह संदेश आज विश्व के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख और कारगिल जैसे विविधताओं से भरे स्थानों में यह संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। यह विरासत आज भी हमें बताती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही हमें अंतिम समाधान दे सकता है। श्री शाह ने कहा, ''जब तक व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। आध्यात्मिक साधना के बिना ज्ञान अधूरा है, जबकि ज्ञान के बिना आध्यात्मिक साधना दिशाहीन है। इसलिए आध्यात्मिक साधना और ज्ञान का संगम ही सही मार्ग है। इन सबके बाद भी यदि नैतिक अनुशासन नहीं है, तो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। ज्ञानमय जीवन का आधार नैतिक अनुशासन है।''■

बौद्ध दर्शन और कला का प्राचीन केंद्र है लद्दाख

श्री शाह ने कहा कि आज भी पूरी दुनिया में जहां-जहां बौद्ध परंपरा है, वहां लद्दाख से संवर्धित हुआ यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। सम्राट अशोक के दूतों ने लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। कुषाण काल में लगभग पहली और तीसरी सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा। कई प्राचीन स्तूप, बौद्ध प्रतिमाएं, खरोष्टी-ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि इस काल में भी बौद्ध धर्म यहां आगे बढ़ा। श्री शाह ने कहा कि सिल्क रूट के कारण भी कश्मीर, लेह, यारकंद, खोतान और तिब्बत को जोड़ने वाले मार्ग सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि विचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बना। उन्होंने कहा कि सातवीं से 10वीं सदी में महायान और वज्रयान परंपराएं तिब्बत से लद्दाख पहुंची और यहां पर तथागत का संदेश समृद्ध हुआ। इसके बाद निर्णायक योगदान 10वीं व 11वीं सदी में आया जब संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। 108 मठों की स्थापना हुई, अलची मठ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म को संस्थागत और स्थाई स्वरूप दिया गया।

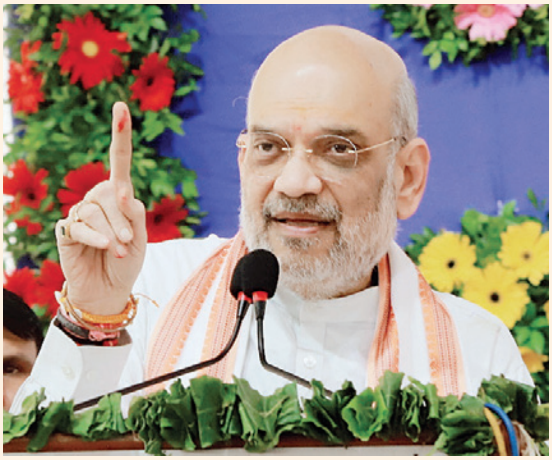

सिक्किम की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक फोकस

जैविक व प्राकृतिक खेती का सिक्किम मॉडल पूरे देश के लिए है प्रेरणा

सहकार जागरण टीम

सिक्किम के गांव-गांव तक पहुंच रही सड़क

सिक्किम में पर्यटन रोजगार का एक प्रमुख साधन है। इससे बड़ी मात्रा में आय होती है और और पर्यटन तभी फलता-फूलता है जब इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हाल के वर्षों में राज्य में सैकड़ों किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है और हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अब एक वास्तविकता बन रहा है। हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिक्किम को पूरे देश से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में बागडोगरा-गंगटोक एक्सप्रेस-वे और सेवक-रंगपो रेल लाइन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है और गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी आवश्यक भावी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। इस दिशा में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जैविक खेती में किए गए सिक्किम के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देमाजोंग अब न केवल चावल उत्पादन के लिए बल्कि जैविक चावल के लिए भी जाना जाता है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकैडो और कीवी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच रहे हैं, जबकि सैकड़ों प्रकार के औषधीय पौधे स्थानीय लोगों के लिए आय का स्रोत बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक जैविक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। जैविक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा है। सिक्किम के लोगों की जीवनशैली और संकल्प राष्ट्र के विजन का हिस्सा बन चुके हैं।

सेवोक-रंगपो रेल लाइन का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसे 2008-09 में स्वीकृत तो किया गया, लेकिन यह परियोजना फाइलों में अटकी रही और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। केंद्र में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास ने फिर से गति पकड़ी है और पहली बार सिक्किम में रेल पहुंच रही है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भलेधुंगा, येन-येंग और पेलिंग में रोपवे के निर्माण, भलेधुंगा में बन रहे स्काईवॉक और सिंगशोर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काईवॉक की तैयारियों को नवोन्मेषी सोच के उदाहरण के रूप में पेश किया। नाथुला और नमली जैसे स्थानों पर सीमावर्ती क्षेत्रों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी काम चल रहा है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन आसान होगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर तेजी से बदल रहे विश्व के नजरिए का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया का ध्यान सतत जीवनशैली, स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। पूर्वोत्तर और सिक्किम इस भावी विकास के प्रमुख केंद्र हैं। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। वर्ष 2016 में सिक्किम ने खुद को पूरी तरह से जैविक राज्य घोषित किया। यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ■

मुंबई में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर 25000 ड्राइवर हुए ऑनबोर्ड

सहकार जागरण टीम

हमारे देश में समाज के सभी वर्गों के आर्थिक-सामाजिक विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में सहकारिता की जड़ें मजबूत और गहरी हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय निरंतर प्रभावी कदम उठा रहा है। इनमें भारत टैक्सी सेवा का अभिनव पहल भी एक ऐसा दूरगामी कदम है जो शहरी परिवहन को सहकारी और तकनीक-आधारित मॉडल के जरिए नई दिशा प्रदान कर रहा है। मुंबई में भारत टैक्सी के डिजीटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 25000 ड्राइवर ऑनबोर्ड हो चुके हैं।

ऑनबोर्डिंग अभियान का मुंबई में हुआ उद्घाटन

दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ के साथ भारत टैक्सी के सक्रिय शहरों में अब शामिल हुआ मुंबई महानगर

अब तक 5.17 लाख से अधिक ड्राइवर और 50 लाख से ज्यादा यात्री भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़े

सारथी के कल्याण, डिजिटल सशक्तीकरण और संगठित शहरी गतिशीलता प्रणालियों के विस्तार पर केंद्रित है भारत टैक्सी

भारत टैक्सी से प्रतिमाह लगभग 10 लाख राइड की जा रही हैं पूरी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद श्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब से भारत टैक्सी के विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसमें सैकड़ों ऑटो-रिक्शा एवं कैब चालक, परिवहन यूनियन प्रतिनिधि एवं सहकारी संघों के सदस्य शामिल हुए। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत टैक्सी का विस्तार करना है, जिससे सारथियों की भागीदारी बढ़ेगी, पारदर्शिता में सुधार होगा और उन्हें बेहतर आय के अवसर उपलब्ध होंगे। दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़

पारदर्शिता और सारथियों के श्रम की गरिमा को महत्व

भारत टैक्सी एक सहकारी मॉडल पर आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें सारथियों को भागीदार माना जाता है, न कि केवल सेवा प्रदाता। यहां सारथियों को भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। भारत के विकसित हो रहे गतिशीलता तंत्र को मजबूत बनाने में सहकारी और प्रौद्योगिकी-आधारित मॉडल का यह ऑनबोर्डिंग अभियान प्रमुख शहरों में चालक-प्रथम गतिशीलता प्रणालियों को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इसमें पारदर्शी कमीशन, बेहतर आमदनी और सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित किया गया है। यह सेवा भारत टैक्सी चालकों को भागीदार के रूप में जुड़ने का अवसर देती है, साथ ही उन्हें ऐसे डिजिटल उपकरणों का लाभ मिलता है जो पारदर्शिता, आय और श्रम की गरिमा को बढ़ा सकते हैं। ऐसी पहलें भारत की शहरी परिवहन प्रणालियों की भविष्य दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

और लखनऊ जैसे शहरों में इस टैक्सी सेवा के संगठित मोबिलिटी नेटवर्क के तेजी से बढ़ने के साथ ही अब मुंबई में भी इस सेवा का विस्तार हो गया है। भारत टैक्सी का तेजी से हो रहा यह प्रसार श्री अमित शाह के उस विजन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने आगामी तीन वर्षों में देश के सभी प्रमुख शहरों तक भारत टैक्सी के विस्तार का आह्वान किया है। ऐसे में भारत टैक्सी की मुंबई में पहल राष्ट्रीय विकास रोडमैप का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर उभरा है।

टैक्सी चालकों (सारथियों) की आजीविका में सुधार और यात्रियों को भी अवांछित आर्थिक अधिभार से राहत देने वाला यह महत्वपूर्ण कदम सरकार के उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाकर, परिचालन दक्षता में सुधार कर और राइड की मांग तक अधिक नियमित पहुंच सुनिश्चित करेगा। भारत टैक्सी सेवा प्लेटफॉर्म से जहां अबतक 5.17 लाख से अधिक चालक जुड़े चुके हैं, वहीं 50 लाख से अधिक ग्राहक ऑनबोर्ड हो चुके हैं। दिल्ली और गुजरात सहित देश के विभिन्न शहरों में भारत टैक्सी से हर महीने लगभग 10 लाख राइड संचालित की जा रही हैं।

लाखों ऑटो-रिक्शा व कैब सारथियों की बेहतर आजीविका

शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करने और चालकों की आजीविका में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुंबई में भारत टैक्सी चालक ऑनबोर्डिंग पहल के उद्घाटन से देश के अन्य हिस्सों के साथ ही अब मुंबई में लाखों ऑटो-रिक्शा और कैब सारथियों की बेहतर आजीविका सुनिश्चित होगी। सारथियों के समग्र कल्याण के साथ ही सहकारी टैक्सी सेवा को जनसुलभ बनाने का अभियान अपने नए पड़ाव पर पहुंच गया है।

प्रौद्योगिकी-आधारित, समावेशी और सहकारी गतिशीलता ढांचे को बढ़ावा

मुंबई में भारत टैक्सी के परिचालन को सारथियों और महानगर के यात्रियों के लिए सार्थक निर्णय के रूप में व्यक्त करते हुए टैक्सी सेवा के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री विवेक पांडेय ने कहा कि मुंबई एक उच्च संभावनाओं वाला बाजार है, जहां स्थानीय चालक यूनियनों से मिले मजबूत समर्थन ने शहर में इस सहकारी प्लेटफॉर्म के विस्तार तथा सारथियों के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम के निर्माण के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। मुंबई में भारत टैक्सी का यह विस्तार महानगरीय क्षेत्रों में सारथियों और यात्रियों की बदलती जरूरतों के अनुरूप है और यह प्रौद्योगिकी-आधारित, समावेशी और सहकारी गतिशीलता ढांचे को बढ़ावा देने की भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सरकार के नीतिगत दूरगामी पहल और उसके सफल कार्यान्वयन का ही परिणाम है, क्योंकि भारत टैक्सी सेवा शुरू होने के कुछ ही महीनों के भीतर मुंबई जैसे महानगर में इसका विस्तार देशभर में शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करने और चालकों की आजीविका में सुधार की दिशा में सरकार के संकल्प को बल दे रहा है।

सहकारिता के चिंतन की उपज है भारत टैक्सी

सहकारी चिंतन और सामुदायिक विकास से प्रेरित भारत टैक्सी अपनी वैचारिक और बुनियादी स्तर पर ही ओला और उबर जैसे निजी कंपनियों की केवल लाभार्जन की सोच से बिल्कुल अलग है। यहां निजी टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों के द्वारा ड्राइवरों के शोषण, मनमाने कमीशन तय करने और असुरक्षित कार्य-परिस्थिति की व्यापक चुनौतियों से उन्हें मुक्ति मिली है और साथ ही यात्रियों के हितों व उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। वास्तव में, यह सहकारी प्लेटफॉर्म उस पूंजीवादी सोच के खिलाफ सरकार से समर्थित एक सहकारी पहल है जहां ओला-उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवरों के शोषण के मॉडल को नकारकर उन सभी सारथियों को मालिकाना हक प्रदान करने की पहल की गई है। भारत टैक्सी ड्राइवरों को भागीदार के रूप में जोड़ती है और उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए पारदर्शिता, बेहतर कमाई और सम्मानजनक काम का अवसर देती है। इस सहकारी मॉडल में यात्रियों को भी अनावश्यक टैरिफ और किराए की मनमानी बढ़ोत्तरी से निजात मिला है। ऐसे में, सरकार समर्थित भारत टैक्सी एक वैकल्पिक और अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के रूप में उभर रही है। इससे आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार देश के अन्य टियर-1 और टियर-2 शहरों तक होने की उम्मीद जगी है।■

महिला सम्मेलन में वाराणसी को 6350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को सरकार प्रतिबद्ध: श्री नरेन्द्र मोदी

- **सरकार ने महिलाओं के कल्याण को दी सर्वोच्च प्राथमिकता**
- **भारत की नारी शक्ति विकसित भारत का मजबूत स्तंभ**
- **सुविधा व सुरक्षा के साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर**

सहकार जागरण टीम

राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। 'नारी शक्ति' 'विकसित भारत' का सबसे मजबूत स्तंभ है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने व नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने महिलाओं के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में 6350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए यह विचार व्यक्त किया। महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके आरक्षण के अधिकार को हकीकत बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। महिला सशक्तीकरण की बदलाव लाने वाली शक्ति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब घर में कोई महिला सशक्त होती है तो पूरे परिवार को ताकत मिलती है और इससे समाज और देश मजबूत होते हैं। पिछड़ी सोच को तोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने बताया कि 25 साल पहले जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने लड़कियों के लिए दो योजनाएं शुरू की थीं-'शाला प्रवेशोत्सव', ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई पूरी करें और 'मुख्यमंत्री कन्या केलवाणी निधि', ताकि उनकी फीस में मदद मिल सके। तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में महिलाओं के कल्याण को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनके हितों के संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के लिए बैंक खाते खोले गए,

2.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए और 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल का पानी पहुंचा। इन पहलों ने बहनों और बेटियों को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखा। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। हर बड़ी योजना के केंद्र में बहनों और बेटियों को रखा गया, जो हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दो साल पहले सिर्फ एक महीने में 27 हजार लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलने और हर खाते में 300 रुपए जमा किए जाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने लड़कियों की शिक्षा को मजबूत किया है, जबकि मुद्रा योजना ने उनकी कमाई सुनिश्चित की है। पहली बार पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों बहनों के नाम पर संपत्ति दर्ज हुई है। आज हमारी माताएं और बहनें अपने घरों की मालकिन बन रही हैं। सुविधा और सुरक्षा को सशक्तीकरण की नींव बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित फैसलों के जरिए नया आत्मविश्वास जगाया है। महिला पुलिस थानों और काउंसलिंग केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक सशक्तीकरण के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर-परिवार में उनकी आवाज भी उतनी ही मजबूत हो जाती है। पिछले 11 वर्षों में लगभग 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। अब तक तीन करोड़ बहनें 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। इनमें बनारस की हजारों बहनें भी शामिल हैं।

महिला सशक्तीकरण में डेयरी क्षेत्र के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी से जुड़ी लाखों बहनों को बोनस के रूप में सीधे 106 करोड़ रुपए मिलने पर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है। बनारस आगे बढ़ेगा, बनास डेयरी आगे बढ़ेगी और यह बोनस भी लगातार बढ़ता रहेगा।

'विकसित भारत' के निर्माण के अभियानों की बागडोर महिलाओं को सौंपने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 'बैंकिंग सखियां' डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ा रही हैं, 'इंश्योरेंस सखियां' बीमा से जुड़ी पहलों का नेतृत्व कर रही हैं, 'कृषि सखियां' प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, और 'नमो ड्रोन दीदियां' कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति की अगुवाई कर रही हैं। इसके अलावा सेना, नौसेना, वायुसेना, सैनिक स्कूलों और रक्षा अकादमियों में बेटियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।

सरकार के नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को 'नागरिक देवो भव' के मंत्र के साथ रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई और शिकायत निवारण ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसी भावना के साथ काशी के विकास का विस्तार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से किया गया है। पिछले एक दशक में उत्तरी और पूर्वी भारत के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काशी के उभरने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 बिस्तरों वाला मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल यहां के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इसके अतिरिक्त 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी गई है। इससे काशी में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक विशाल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

काशी में हर तरह के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि काशी और अयोध्या के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी शुरू किए गए हैं। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए दो 'अमृत भारत' ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इससे पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इन पवित्र शहरों तक पहुंचने के लिए आधुनिक कनेक्टिविटी के विकल्प मिलेंगे। इससे यूपी और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिलेगा। लोग आसानी से और सुविधाजनक तरीके से वहां पहुंचकर अपनी धार्मिक व आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति कर पाएंगे। ■

'सहकार से समृद्धि' की दिशा में जयपुर में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने की राष्ट्रव्यापी पहल

सहकार जागरण टीम

सहकारिता ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था के एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय देशभर में क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिससे कि सहकारी क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों को गति दी जा सके। इसी राष्ट्रव्यापी पहल के तहत राजस्थान के जयपुर में प्रथम सहकारी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सहकारी सुधारों के क्रियान्वयन को और तेज करने के साथ ही 'सहकारिता में सहकार' के माध्यम से सहकारी विकास के संकल्प को दोहराया गया। यह कार्यशाला सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां मंत्रालय ने अपने विभिन्न पहलों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने, पेशेवर प्रबंधन और राज्यों एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) जैसी बुनियादी संस्थाओं की सशक्त भागीदारी के माध्यम से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में इन सहकारी पहलों के जरिए देश के सभी गांवों के किसानों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से उनके निकटतम स्तर तक आधुनिक अनाज भंडारण सुविधाओं को पहुंचाने की योजना को गति दी जा रही है। कार्यशाला का मुख्य फोकस विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की प्रगति, कार्यान्वयन रणनीति और राज्यवार लक्ष्यों पर रहा। इसमें पैक्स की पहचान, परियोजना क्रियान्वयन और पांच लाख टन से 50 लाख टन भंडारण क्षमता हासिल करने के अंतर-एजेंसी समन्वय पर विशेष चर्चा हुई।

- **सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन जैसे- विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना, पैक्स के डिजिटलीकरण व विस्तार तथा डेयरी एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं के विस्तार पर जोर**
- **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्यवार कार्य योजनाओं पर भारत सरकार का विशेष फोकस**

'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस

पैक्स के नेटवर्क को पारदर्शी, सशक्त एवं विस्तारित करने के साथ ही सहकारी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया है। इसके साथ ही, सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं लाभार्थियों के कल्याण के लिए 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस है। 'सहकार

ग्रामीण समृद्धि, रोजगार सृजन तथा समावेशी आर्थिक विकास

नाबार्ड के अध्यक्ष, सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण समृद्धि, रोजगार सृजन तथा समावेशी आर्थिक विकास के प्रमुख आधार के रूप में सशक्त बनाने पर जोर दिया। कार्यशाला के एक प्रमुख सत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड), नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ), सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्लूसी) और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (एसडब्लूसी) के प्रतिनिधियों ने गोदाम विकास की प्रगति पर अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश की, जिनमें गोदाम के लिए स्थान चयन, जिलावार उसकी जरूरतों, किराया तंत्र, संकेतात्मक दरों तथा भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन की योजनाएं शामिल थीं। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा पर विशेष चर्चा के दौरान पैक्स को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत जोड़ने की प्रक्रिया, सरलीकृत प्रक्रियाओं, पात्रता मानदंड, प्रशिक्षण सहयोग तथा सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध लाभों की जानकारी दी गई।

से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए संकल्पित सहकारिता मंत्रालय की इस कार्यशाला में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला प्रमुख सहकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा तथा पैक्स, डेयरी सहकारी संस्थाओं, मत्स्य सहकारी संस्थाओं एवं देशभर में भंडारण अवसंरचना की पहुंच और कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु व्यावहारिक रणनीतियों को अंतिम रूप देने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुई।

सहकारी नीतियों की समीक्षा, प्रगति आकलन, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान तथा जमीनी स्तर पर सहकारी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजनाओं की तैयारी के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में आयोजित इस कार्यशाला में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं की निगरानी, कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कार्यान्वयन, पैक्स की पहचान, भूमि चयन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी तथा संचालन समन्वय पर विचार-विमर्श किया गया, जहां राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने सितंबर 2026 और सितंबर 2027 तक अनाज भंडारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी कार्ययोजनाएं भी प्रस्तुत कीं।

एम-पैक्स के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर जोर

वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स) के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर विमर्श के दौरान भागीदार राज्यों ने नई समितियों के गठन, पंजीकरण, संबद्धता एवं व्यवसाय विकास के लिए जिलावार लक्ष्य साझा किया। पैक्स के ऋण गतिविधियों के विस्तार, जमा राशि में वृद्धि, व्यवसायों में विविधता तथा सहकारिता मंत्रालय के सुनियोजित नेतृत्व के माध्यम से पैक्स की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। डेयरी एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं पर आयोजित चर्चा के दौरान मौजूदा सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, सदस्यता वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाने और खरीद प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके साथ ही, देशभर की कमजोर सहकारी संस्थाओं के पुनर्जीवन तथा संस्थागत वित्तीय प्रणालियों से उनके एकीकरण पर भी विमर्श किया गया, जिससे कि सहकारिता की सभी ईकाइयों को सुदृढ़ किया जा सके। सहकारी ढांचे को सशक्त करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों, पशुपालकों व मछुआरों की आय बढ़ाने का भी यह एक प्रभावी मंच साबित हुआ। निश्चय ही इस कार्यशाला के निष्पादन से सहकारी सुधारों के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी और सहकारी आंदोलन सार्थक रूप से आगे बढ़ेगा।■

नई संभावनाओं, नए सपनों और नए अवसरों का द्वार है गंगा एक्सप्रेस-वे : पीएम श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

- **मां गंगा के निकट से गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे उत्तरप्रदेश के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा**
- **उत्तरप्रदेश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस-वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अपार संभावनाओं को भी लाता है करीब**
- **एक्सप्रेस-वे से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हो सकेगी राज्य के किसानों की पहुंच**

लगभग 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक केंद्रों को मध्य उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ेगा। इससे 12 जिलों के करोड़ों नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ एक तेज रफ्तार सड़क नहीं है, यह नई संभावनाओं, नए सपनों और नए अवसरों का द्वार है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करते हुए कही। कृषक समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपजाऊ क्षेत्रों के किसान ऐतिहासिक रूप से अपर्याप्त रसद अवसंरचना और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के कारण प्रमुख बाजारों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं। अब बेहतर कनेक्टिविटी से वे अपने कृषि उत्पादों को देश व प्रदेश के विभिन्न बाजारों तक समय से पहुंचा सकेंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

एक्सप्रेस-वे के कनेक्टिविटी लाभों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अपार संभावनाओं को भी करीब लाता है। इसके किनारों पर वाहनों के दौड़ने के साथ-साथ नए औद्योगिक अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेस-वे के साथ उभरते औद्योगिक अवसरों पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि हरदोई जैसे जिलों में रणनीतिक रूप से औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है, ताकि फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, हथकरघा, चमड़े के सामान और हस्तशिल्प जैसे उद्योगों को आकर्षित किया जा सके और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। मुद्रा योजना और ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) जैसी योजनाओं से सशक्त राज्य के युवाओं की उद्यमशीलता की भावना की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने

कहा कि लघु उद्योगों और एमएसएमई को बढ़ावा मिल रहा है और बेहतर कनेक्टिविटी उनके लिए नए रास्ते खोलेगी। इन सभी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बड़े पैमाने पर पहुंच बनेगी। इससे लाखों परिवारों की आय में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कभी पिछड़ा और 'बीमारू' कहलाने वाला यह राज्य आज एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राज्य की अपार क्षमता और देश की विशाल युवा आबादी की अपार संभावनाओं के कारण यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस शक्ति का उपयोग यूपी को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है, जहां नए उद्योग और कारखाने स्थापित किए जाएंगे, बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, जिसका आधा उत्पादन यूपी में होता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में राज्य की उभरती भूमिका पर प्रधानमंत्री ने नोएडा में सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य भविष्य की एआई आधारित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के दो रक्षा गलियारों में से एक इस राज्य के भीतर से होकर गुजरता है, जहां प्रमुख रक्षा निर्माता इकाइयां स्थापित हैं। जैसी विश्व स्तर पर प्रशंसित ब्रह्मोस मिसाइलें यहां बन रही हैं। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत के लिए एक रणनीतिक शक्ति बन रहा है।

राज्य में कनेक्टिविटी के व्यापक विस्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस समय राज्य में 21 हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। इनमें पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को एक मिसाल बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब इसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। भारत की व्यापक सभ्यतागत और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विकास को रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य का परिवर्तन राष्ट्र के मूल संकल्प को साकार करता है। आज पूरा देश एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है - विकसित भारत का संकल्प! इस संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

बाहरी खतरों के बावजूद विकास के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि विकास की नई उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे को इस व्यापक विकास प्रतिमान का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों पर भरोसा जताया कि वे उभरते अवसरों को वास्तविक समृद्धि में बदल देंगे। मुझे विश्वास है कि गंगा एक्सप्रेस-वे जो अवसर लेकर आएगा, उत्तर प्रदेश के लोग उन अवसरों को अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से साकार कर देंगे।

मां गंगा के शाश्वत महत्व और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बीच तुलना करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास में एक्सप्रेस-वे की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया। इन नवनिर्मित राजमार्गों को विकासशील भारत की जीवनरेखा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये आधुनिक जीवनरेखाएं आज भारत के उज्ज्वल भविष्य की घोषणा कर रही हैं। वर्तमान सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को अभूतपूर्व रूप से तेज किया है। तीव्र गति से आधुनिकीकरण के अपने विजन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्तमान सरकार के काम की गति है! यह वर्तमान सरकार के काम करने का तरीका है। ■

इटली और भारत के बीच 2029 तक 20 बिलियन यूरो व्यापार का लक्ष्य : पीएम श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच व्यापार व निवेश बढ़ाने का एक मार्ग सुनिश्चित करता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक इटली और भारत के बीच 20 बिलियन यूरो से अधिक व्यापार का लक्ष्य है। इसमें डिफेंस, एयरोस्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एग्री-फूड, टूरिज्म आदि पर फोकस किया जाएगा। ये बातें इटली की प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोम में कही। 'मेड इन इटली' को हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का दूसरा नाम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब इसका 'मेक इन इंडिया' पहल के उच्च गुणवत्ता के साथ स्वाभाविक तालमेल होगा। दोनों देशों के बीच बढ़ती कारोबारी घनिष्ठता का प्रमाण इटली में एक हजार से अधिक भारतीय उद्योगों की मौजूदगी है। इसी प्रकार इटली के कारोबारी भी भारत में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं।

तकनीकी नवाचार को दोनों देशों के बीच संबंधों का केंद्र बिंदु बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशक एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति से आकार लेंगे जिसका दायरा बहुत बड़ा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जरूरी मिनरल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में तरक्की होगी। भारत का डायनामिक इनोवेशन इकोसिस्टम, कुशल प्रोफेशनल टैलेंट पूल और इटली की एडवांस्ड इंडस्ट्रियल क्षमताएं हमारे सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती हैं। हमारे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप इसमें मदद करेगी।

- **डिफेंस, एयरोस्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एग्री-फूड और टूरिज्म पर फोकस**
- **एआई को जिम्मेदार और मानव केंद्रित बनाने को लेकर इटली व भारत लंबे समय से मिलकर कर रहे काम**

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव दुनिया के देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच के पड़ने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इटली और भारत लंबे समय से यह तय करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि एआई का विकास ज़िम्मेदार और इंसान-केंद्रित हो। इस नजरिए से भारत और इटली एआई को समावेशी विकास के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में देखते हैं। एआई विभिन्न देशों के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी गैप को कम कर सकता है। इंसान केंद्रित भारत के 'मानव विजन' और मानवीय मूल्यों पर आधारित इटली के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि हमारी पार्टनरशिप लोगों के सशक्तीकरण में एक प्रेरक की भूमिका अदा करे। हमारा दृष्टिकोण भारत के डिजिटल स्केल को इटली के औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है और यह तय करता है कि तकनीक मानव गरिमा का सम्मान और सेवा करे। हमारा मकसद एक खुला और भरोसेमंद व सबकी समान पहुंच वाला डिजिटल स्पेस बनाना है, ताकि दुनिया का प्रत्येक देश एआई का फायदा उठा सके। श्री मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आ रहे बदलाव के बीच भारत और इटली के बीच संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और सैटेलाइट तकनीक में भारत की विशेषज्ञता इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की बेहतरीन खूबियों के साथ मिलकर काम करने और अगली पीढ़ी की तकनीक के विकास के लिए बड़े मौके देती है। ■

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 की सफलता

शुद्ध, पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण मसालों का बड़ा केंद्र बना जयपुर

सहकार जागरण टीम

जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सहकारी मसाला उद्यमियों ने की 5.50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मसालों एवं अन्य उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री

सहकारी क्षेत्र में देशभर में नया विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प से पूरा करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय विविध प्रकार से सहकारी संस्थाओं की सामर्थ्य बढ़ाने और उन्हें सक्षम व्यावसायिक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए बहुआयामी कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके परिणाम के रूप में हमारी सहकारी समितियां सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 10 दिवसीय 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' की सफलता इसका एक ज्वलंत प्रमाण है, जहां राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं ने अपनी भागीदारी के माध्यम से लोगों को शुद्ध मसाले, कृषि उत्पादों और घरेलू वस्तुएं सुलभ कराने की एक मिसाल कायम की। मिलावट रहित गुणवत्तापूर्ण मसाले और विविध उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुए, जहां 160 स्टालों की सहकारी प्रदर्शनी में जहां उच्च गुणवत्ता वाले मसालों के साथ ही श्री अन्न (मिलेट्स) उत्पादों, ऑर्गेनिक उत्पादों, जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं, तेल, अनाज व हस्तनिर्मित वस्तुओं और घरेलू उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। वहीं, हजारों लोगों ने मेले में भागीदारी करके 5.50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मसालों और अन्य बहुत से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की रिकॉर्ड खरीदारी भी की। सहकारी क्षेत्र के लिए यह एक उत्साहजनक उपलब्धि है क्योंकि पिछले वर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में 3.25 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी।

सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2003 से लगातार आयोजित किया जा रहा यह मसाला मेला जयपुर की एक विशिष्ट पहचान बन चुका है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद उत्पाद उपलब्ध कराना है।

देशभर के मसाले और सहकारी उत्पादों ने ध्यान आकृष्ट किया

समाज में कोऑपरेटिव की बढ़ती स्वीकार्यता और सहकारी उत्पादों के उत्तम होने के कारण इनकी मांग बढ़ती जा रही है। जवाहर कला केंद्र में मसालों के महाकुंभ में लोगों ने न केवल राजस्थान, बल्कि देश के सभी राज्यों से मसालों की महक महसूस की। मेले में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की सहकारी समितियों के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहे, जहां केरल की काली मिर्च और लौंग, तमिलनाडु की हल्दी और दालचीनी, आंध्र प्रदेश की लाल मिर्च और काजू, कश्मीर के केसर और ड्राई फ्रूट्स, पंजाब के चावल और 'रेडी-टू-ईट' उत्पाद और मध्य प्रदेश का सिहोरी गेहूं लोगों ने बहुत पसंद किया। वहीं, राजस्थान के कई प्रसिद्ध उत्पाद जैसे मथानिया की मिर्च, नागौर का जीरा, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठंडाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शरबत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर दाल और बीकानेर के पापड़ भी लोगों के मुख्य आकर्षण केंद्र बने रहे। साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पाद भी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में लोगों के ध्यानाकर्षण के मुख्य केंद्र बने रहे। सरकार और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से यह मेला न केवल व्यापार और बिक्री का माध्यम बना, बल्कि इसने ग्रामीण उत्पादकों, महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों को भी एक मजबूत मंच प्रदान किया। इससे उनके उत्पादों को एक ही जगह पर व्यापक बाजार मिला, जो कि उनके आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बना। ■

असम में महिला किसानों को समृद्ध बना रहा स्वरंग एफपीओ

सहकार जागरण टीम

ग्रामीण भारत में सहकारी समितियों का विस्तार किसानों की समृद्धि का आधार बन रहा है। गांवों की महिलाएं भी इन सहकारी संगठनों से जुड़कर कृषि विकास के क्षेत्र में एक मिसाल पेश कर रही हैं। महिलाओं की आर्थिक दशा को उन्नत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में सक्रिय स्वरंग महिला किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय बिचौलियों के शोषण से महिला किसानों को मुक्ति दिलाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार सुलभ कराकर उनकी आय दोगुनी करने वाली यह सहकारी समिति राज्य के उदलगुरी जिले के देउरी गांव व बेचिमारी क्षेत्र में सक्रिय है। यह महिला किसानों द्वारा संचालित है और महिला सशक्तीकरण, क्षमता निर्माण और सतत आजीविका के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। यह संगठन छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट कर उनकी उपज को बेहतर बाजार तक पहुंचाने, खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके जरिए छोटी-सीमांत महिला किसानों को बेहतर इनपुट, बाजार और आय के अवसर मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य किसानों के लिए यह एफपीओ प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

स्थानीय किसानों को संगठित करने और सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित स्वरंग महिला एफपीओ मुख्य रूप से जूजूबे व बेर, बकवीट, चावल, मक्का और सरसों आदि कृषि उत्पादों और विशिष्ट जैविक फसलों की खरीद-बिक्री में महिला किसानों की सामर्थ्य बढ़ा रही है। यह एफपीओ किसानों को बीज व खाद की इनपुट सप्लाई के साथ ही मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, बाजार लिंकेज बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी योगदान कर रहा है। मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण से एफपीओ ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके सदस्य महिला किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्वरंग ने स्थानीय बाजारों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच बनाई है और कुछ उत्पादों का निर्यात भी शुरू किया है। जैविक खेती और जल संरक्षण जैसी प्रथाओं को अपनाकर स्वरंग ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शुरुआती दिनों में इस एफपीओ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमित संसाधनों, बाजार की जानकारी की कमी और किसानों में जागरूकता के अभाव के बावजूद स्वरंग किसान संगठन ने इन समस्याओं का डटकर मुकाबला किया। इस एफपीओ ने किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए कई नवाचार किए हैं, जिससे बिचौलियों की महिलाओं के शेयरहोल्डिंग भूमिका कम हुई है। यह किसान संगठन खेती में बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही साथ टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान कर रहा है। यह विकासशील एफपीओ महिलाओं की आय बढ़ाने और सामुदायिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने महिला किसानों के कृषि उत्पादों के व्यावसायिक टर्नओवर बढ़ाने, ट्रेनिंग और मुर्गी पालन व मशरूम आदि की खेती के जरिए उनकी स्थायी आजीविका पर जोर दिया है। एफपीओ की मुख्य कार्यकारी जयंती बोरो के नेतृत्व में इस महिला-केंद्रित एफपीओ ने सदस्य महिलाओं को शेयरहोल्डिंग, बोर्ड में भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है।■

बनारस के आठ गांवों के किसानों का समूह दूसरों के लिए बना मिसाल

सहकार जागरण टीम

संगठन और सहयोग के अभाव में कभी दर-दर भटकने वाले किसानों को जब सहकार का साथ मिला तो उनके जीवन में समृद्धि छा गई। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक में स्थित कृषक उत्पादक संगठन एवं उद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड के सहयोग से छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। 26 फरवरी 2024 को निगमित इस एफपीओ की स्थापना वास्तव में 2021 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और बागवानी विभाग के सहयोग से हुई थी। वर्तमान में 1785 किसान इसके सदस्य हैं। यह इलाके के टिकारी, रमाना, तारापुर, सरायडेंगारी, मुरादेव, माधोपुर, बेतावर और बेताबार छितौनी जैसे 8 गांवों में मजबूती से सक्रिय है।

जैविक फसलों को प्रसंस्कृत कर बाजार में बेचने और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार से बदली तस्वीर

मुख्यत सब्जियों भिंडी, मिर्च, बैगन के साथ ही केला, अमरूद, आम जैसे फलों की खेती और डेयरी फार्मिंग करने वाले इलाके के छोटे और सीमांत किसान इसके पहले गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। उचित कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण फल और सब्जियों की बर्बादी हो जाती थी। बिचौलियों के दबदबे के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। आधुनिक तकनीक तक पहुंच न होने और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण किसान पारंपरिक खेती में ही सिमटे रहते थे। कृषक उत्पादक संगठन ने इन सभी समस्याओं का व्यापक समाधान प्रस्तुत किया। संगठन ने सबसे पहले बुनियादी ढांचे का विकास किया और मसाला प्रसंस्करण इकाई, सब्जी डिहाइड्रेशन यूनिट, बायोमास आधारित कोल्ड रूम और दो सोलर कोल्ड रूम की स्थापना की। परिवहन की समस्या के समाधान के लिए कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन की भी व्यवस्था की गई। किसान अपने उत्पादों का प्रसंस्करण कर रहे हैं। कच्ची फसल बेचने की बजाय अब वे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि का उत्पादन कर रहे हैं। टमाटर, भिंडी, बैंगन, प्याज की डिहाइड्रेशन की जा रही है। इससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है और बेहतर मूल्य मिल रहा है। डेयरी सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। दूध के साथ-साथ पनीर, घी और फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन शुरू हुआ है। वमीर्कंपोस्ट और बायो-फर्टिलाइजर का उत्पादन कर किसान जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

गतिविधियों में गुणात्मक बदलाव आने के साथ ही एफपीओ की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां इसका कुल व्यापारिक टर्नओवर केवल 28.30 लाख रुपए था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 300.90 लाख रुपए हो गया। शुद्ध परिचालन लाभ भी 2.50 लाख से बढ़कर 5.95 लाख रुपए हो गया। इसके चलते संगठन से जुड़े किसानों की वार्षिक आय में औसतन 8,000 से 15,000 रुपए की वृद्धि हुई है। बल्क में खरीदारी के कारण इनपुट की लागत में 12 से 18 प्रतिशत की कमी आई है। उन्नत कृषि पद्धतियों के अपनाने से मिर्च, अमरूद, टमाटर जैसी फसलों के उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 350 से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूह गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का मौका मिला है। संगठन की ओर से अपने सदस्यों को विभिन्न विधाओं में कुशल बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाता रहा है। इनमें कटाई के बाद प्रबंधन, जैविक खेती, डेयरी प्रबंधन और बाजार संपर्क जैसे विषय शामिल हैं। किसानों को डेयरी प्रसंस्करण केंद्रों, जैविक फार्मों और कृषि तकनीक पार्कों के औद्योगिक भ्रमण भी कराए गए हैं। इससे किसानों में वर्मीकंपोस्ट, फसल चक्र, जैविक कीटनाशकों के उपयोग और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा मिली है। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ एफपीओ के रूप में इसे प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ■

आर रामचन्द्रन

अर्बन कोऑपरेटिव से व्यापक होगा सहकारिता आंदोलन

सहकारिता के नये आयामों ने कृषि, वानिकी, मत्स्य, डेयरी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर पैदा कर दिए हैं। सहकारिता में यदि संभावनाओं की बात करें तो इसका क्षेत्र अभी और भी व्यापक हो सकता है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को लागू करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता में अभूतपूर्व सुधार की शुरुआत की गई। इसके तहत

सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्युटरीकरण समेत डिजिटलीकरण को प्राथमिकता से लागू किया गया। ग्रामीण सहकारिता के साथ शहरी क्षेत्र में भी इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।

डिजिटल सहकारी समितियों के युग में सहकारी पुस्तक समितियों की स्थापना की जा सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में एक अंसारी स्ट्रीट है जहां पुरानी किताबें मिलती है, लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि किसी को पता कैसे चलेगा कि अमुक दुकान पर आपकी पसंद की पुरानी किताब मिलेगी या नहीं? इसके लिए इस क्षेत्र के आसपास के निवासियों या पढ़ने के लिए शहर में आए छात्रों द्वारा एक सहकार बनाया जा सकता है। छात्रों के इस सहकार को पुस्तक के शीर्षकों को बनाए रखने का एक रजिस्टर या डिजिटल तरीका उपलब्ध कराया जा सकता है। अब यदि कोई यह समझना चाहे कि उत्तर प्रदेश की तुलसीदास रामायण और तमिल की कम्ब रामायण में क्या अंतर है? तो ऐसे में सहकारी समितियां मददगार साबित हो सकती हैं। यह बात अलग है कि विद्वान और शोधार्थी आसानी से इसका पता लगा सकते हैं, बावजूद इसके सबके पास इतना समय नहीं होता कि पुस्तकालय जाकर गहन अध्ययन करे। इसलिए यह शहरी सहकार पुस्तकालय के साथ ही सूचनाओं के आदान प्रदान का एक नया आयाम हो सकता है।

हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ लोगों का पलायन होता है। सहकार के क्षेत्र में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जिससे शहरों की तरफ आने वाले इस मानव घनत्व या मानव संसाधन को कोऑपरेशन मॉडल में बदला जा सके। जिससे उनकी क्षमताओं का प्रयोग देशहित में हो सके।

सहकारी क्षेत्र में तीन अतिरिक्त व्यावहारिक मॉडल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि सरकार चाहती है कि शहद के सहकार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि एक प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शहरों में शहद के डिब्बे लगाए जाएं। शहरी क्षेत्र में स्थापित किए गए इन डिब्बों से शहद को घर-घर तक पहुंचाया जा सकता है। केवल शहद का वितरण ही नहीं, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाना चाहिए, जहां मानवीय हस्तक्षेप कम हो और मधुमक्खियों का पालन हो सके। इसके लिए विवादित भूमि का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की भूमि की आमतौर पर निगरानी नहीं की जाती और आम जनता भी इन क्षेत्रों में कम जाती है। ऐसी जगहों को लघु मधुमक्खी पालन यूनिट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इसी तरह बोनसाई वृक्ष उगाने वाली सहकारी समिति में भी कई संभावनाएं हो सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इफको एक पुरानी और प्रशिक्षित कृषि वानिकी सहकारी संस्था है, लेकिन हम इफको की संचालन श्रृंखला में नये आयाम जोड़कर एक आधुनिक फार्म हाउस सहकार बना सकते हैं। एक बदलाव के तौर पर उपहार में बोनसाई पेड़ देने की प्रथा शुरू कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की सामूहिक भागीदारी तय हो सकेगी। शहर की सरकारी और निजी प्रयोग में नहीं आने वाली छतों का उपयोग कई नए प्रयोगों के लिए किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस संदर्भ में बहुत काम किया गया है, लेकिन छतों पर खेती का काम अभी कम ही देखा जाता है। यदि छतों का प्रयोग सहकारी मॉडल के आधार पर खेती या सब्जियों को उगाने के लिए किया जा सके तो इससे शहरी सहकार के अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। एक प्रयास यह भी हो सकता है कि जोमैटो का डिलीवरी मैन जब घर पर खाना डिलीवर करने आए तो हम उसे वापसी में अपने किचन गार्डन या क्लाउड किचन से कुछ सब्जियां देने पर विचार करें। इसी तरह पुलिस थानों, अदालतों या सरकारी कार्यालयों में कबाड़ पड़े पुराने वाहन लॉरी/बस आदि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा बीज के पौधे उगाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्रयोग के दो फायदे हो सकते हैं एक तो पुराने वाहनों का उचित प्रयोग हो सकता है और दूसरा यह कि काम करने के दौरान यदि चारों ओर हरियाली होती है तो इन जगहों पर काम करने वाले लोग ऊर्जावान रहेंगे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में पहली मंजिल पर कुछ पेंटिंग की एक श्रृंखला दिखी जिसमें पेंटिंग को बनाने वाले सभी क्षेत्रीय कलाकारों के नाम थे। इसी आधार पर कलाकार या बौद्धिक समूह के सहकार का भी गठन किया जा सकता है।

निदेशक, इफको

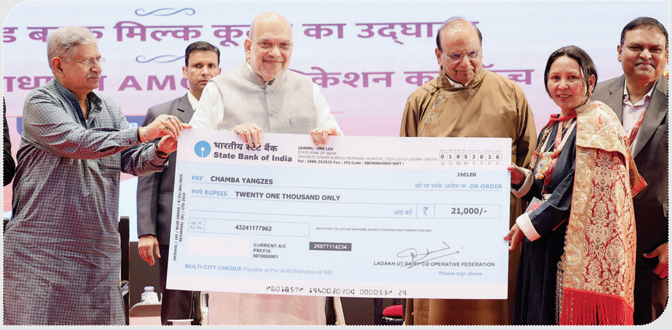

लद्दाख में आयोजित सहकारी डेयरी पैक्स को केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पांच प्रमुख प्रोग्रेसिव डेयरी सोसाइटियों को सम्मानित किया। इस अवसर उन्होंने प्रत्येक सोसाइटी को 21-21 हजार रुपए प्रदान किया।

गंगासागर स्थित कपिल मुनि आश्रम में महर्षि कपिल के ज्ञान, त्याग और तप के प्रतीक ऋषिवर कपिल के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने और देशवासियों के कल्याण की कामना करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह।

सहकारिता मंत्रालय में सचिव श्री आशीष भूटानी ने चावल , सरसों तेल और रेडी टू ईट जैसे उत्पादों की वैश्विक मांग को पूरा करने को लेकर सहकारी संस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा की। सभी प्रमुख सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते हुए सभी पक्षकार।

गुजको-बुकाली मैंगो फेस्टिवल में केसर आम की खेप दुबई रवाना करने के बाद कोआपरेटिव के दिग्गज नेता श्री दिलीप संघाणी अपने सहकारिता के सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा आम निर्यात से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

मध्य प्रदेश के सहकारी किसानों और पशु पालकों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी संस्थाएं आगे आई। किसान कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को पुरस्कृत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव।

एनसीयूआई के राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र के त्रिभुवन सहकारी विश्विद्यालय (टीसीयू) से संबद्धता के आवेदन पर विचार करने के बाद उसके कैंपस का निरीक्षण करने टीसीयू की एक उच्च स्तरीय समिति ने दौरा किया। समिति के अध्यत्र प्रो. श्याम सिंह और प्रो. अंकुर श्रीवास्तव ने यहां लोगों से विचार-विमर्श किया। एनसीयूआई की ओर से राजीव शर्मा, आशीष द्विवेदी रितेश डे और संध्या कपूर समेत अन्य लोगों ने अपना पक्ष रखा।

भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है, और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं, तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारीशक्ति है। जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है, तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद होती जाती है। इसलिए, सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ-साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। बीते 11 वर्षों में देश की करीब 10 करोड़ बहनें 'सेल्फ हेल्प ग्रुप्स' में जोड़ी गई हैं। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही प्रयासों से अब तक तीन करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी अभियान को गति देने में हमारे डेयरी सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

NCUI हाट

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

HINDI

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

RNI No.: DLHI/25/A0141
Published on 15.06.2026 | Postal Registration No DL-SW-01/4214/2023-24
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ